>

Title: Need to issue clear-cut guidelines regarding Teacher Eligibility Test in respect of teachers recruited by States.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): शिक्षा का अधिकार (आरटीई) लागू करते समय क्या मानव संसाधन मंत्रालय ने सभी राज्यों को यह निर्देशित किया कि यदि पूर्व में भी किसी राज्य ने टीचर की भर्ती करते समय एक या दो पात्रता की परीक्षा ली है तो भी शिक्षा का अधिकार लागू होने के बाद टीचर ईलेजिब्लिटी टेस्ट लेना ही होगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बी.एड. से पहले पीटीईटी परीक्षा फिर बी.एड. परीक्षा फिर उन राज्यों की लोक सेवा आयोग के द्वारा भी परीक्षा ली जाती है, ऐसे में क्या टैट की परीक्षा का निर्देश क्या मानव संसाधन मंत्रालय ने जारी किया है कि राज्य चाहे अध्यापक की भर्ती के लिए कैसी भी परीक्षा लें, लेकिन भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत टैट की परीक्षा आवश्यक रूप से ली जाएगी। राज्यों में एक से आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई दो स्तरों पर की जाती है। एक स्तर पर वो स्कूल आते हैं जो कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल होते हैं, इन स्कूलों में टैट आवश्यक किया गया है। इसके अतिरिक्त दूसरे स्तर में कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल होते हैं उसमें भी कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई करवाई जाती है यहां भी थर्ड ग्रेड के टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन यहां टैट आवश्यक नहीं की गई है, तो क्या मंत्रालय का ऐसी विसंगति की ओर भी कभी ध्यान गया है और यदि गया है तो मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों को क्या दिशा निर्देश जारी किये हैं। सभी राज्यों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के साथ-साथ प्राईवेट स्कूलों में भी छात्रों की संख्या दो गुनी, तीन गुनी या कहीं कहीं चार गुनी है। प्राईवेट स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापकों पर टैट किस तरह से लागू होगा यह समझ से परे है। आरटीई के नियम 23 (2) यद्यपि टैट में पांच साल तक की छूट के लिए प्रावधान किया हुआ है फिर भी केन्द्र सरकार के स्तर पर कितने राज्यों को छूट दी गई है इसकी जानकारी अभी तक नेट पर उपलब्ध नहीं है। टैट की परीक्षा का प्रावधान विसंगतियों से भरा हुआ है तथा राज्य सरकारें असमंजस की स्थथित में अध्यापकों की भर्ती नहीं कर पा रही है। अतः ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मांग करता हूं कि जिन राज्यों में अध्यापकों की परीक्षा लेने की प्रक्रिया पहले से ही मौजूद है ऐसे में टैट की अनिवार्यता लागू करने के बारे में मंत्रालय टैट की बारे में स्थिति स्पष्ट करने की व्यवस्था करे।